

युवाओं और महिला समूहों का होगा कौशल विकास

कौशल विकास मिशन ने 13 विभागों को भेजा प्रशिक्षण का प्रस्ताव
इनसे जुड़े युवाओं, महिलाओं को तीन महीने का मिलेगा प्रशिक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में कौशल विकास की पहुंच समाज के हर वर्ग तक सुनिश्चित करने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं और महिलाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया है। इसके तहत 13 प्रमुख विभागों को कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रस्ताव भेजा गया है।

मिशन ने इन विभागों से जुड़े युवाओं, शहरी गरीब परिवारों, महिला समूहों, अल्पसंख्यक समुदाय और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी उनकी रुचि अनुसार आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मिशन ने विभागों को पत्र भेजकर तीन महीने के कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा है।

साथ ही उनसे लक्ष्य और कार्ययोजना साझा करने को भी कहा गया है। आगामी तीन महीनों के लिए प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन जून के पहले सप्ताह में होगा। मिशन ने

जेल में बंद युवा भी होंगे प्रशिक्षित

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कारागार प्रशासन व सुधार सेवाएं विभाग से जुड़े युवाओं को भी कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इससे जेलों में बंद युवाओं का पुनर्वास होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। महिला कल्याण, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण और ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे विभागों से जुड़े युवाओं व महिलाओं को भी आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि उनका लक्ष्य सबसे निर्धन परिवारों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।

■ आठ लाख युवा हुए प्रशिक्षित मिशन निदेशक ने बताया कि मिशन का उद्देश्य 14 से 35 साल के युवाओं को अल्पकालीन, रोजगारपरक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण देना है। पिछले 10 वर्षों में मिशन द्वारा 8 लाख 9 हजार 494 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से 3 लाख 4 हजार 810 युवाओं को रोजगार व सेवायोजन के अवसरों से जोड़ा गया है। सभी विभागों के सहयोग से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

इन 13 विभागों को भेजा गया प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, संयुक्त आयुक्त उद्योग, सीएम युवा, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग व हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय।

संबंधित विभागों से प्रस्ताव पर जल्द सहमति देने का आग्रह किया है।

उन्हें अपना नोडल अधिकारी नामित करने को भी कहा गया है।